



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 5 जनवरी, 2022

पौष 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या 2/सी०पी० 449/84-2-2021-क०संख्या-1317087

लखनऊ, 5 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प०आ०-6

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) की धारा 102 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ग)(घ)(ङ) एवं (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद  
नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में - परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2019) से है;

(ख) "राज्य परिषद" का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;

(ग) "जिला परिषद" का तात्पर्य जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

राज्य परिषद का  
गठन, धारा 6 (2)

3—(1) राज्य परिषद एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें उनतीस सरकारी सदस्य और बीस गैर सरकारी सदस्य निम्नवत होंगे:-

सरकारी सदस्य:-

(एक) राज्य सरकार के उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे।

(दो) राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(तीन) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(चार) राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(पाँच) राज्य सरकार के कृषि विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(छः) आयुक्त , खाद्य तथा रसद विभाग।

(सात) राज्य सरकार के परिवहन विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(आठ) राज्य सरकार का प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

(नौ) महाप्रबंधक, दूरसंचार।

(दस) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश।

(ग्यारह) राज्य सरकार के आवास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(बारह) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।

(तेरह) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

(चौदह) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उत्तर प्रदेश।

(पन्द्रह) प्रबंध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश।

(सोलह) राज्य सरकार के राज्यकर विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(सत्रह) प्रबंध निदेशक, राज्य मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

(अठ्ठारह) अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम।

(उन्नीस) क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय मानक संगठन, उत्तर प्रदेश।

(बीस) राज्य समन्वयक, भारतीय तेल निगम, उत्तर प्रदेश।

(इक्कीस) राज्य सरकार के नगर विकास विभाग का यथास्थिति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(बाईस) सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।

(तेईस) मण्डल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ।

(चौबीस) आंचलिक प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम।

(पच्चीस) अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(छब्बीस) राज्य सरकार के सूचना विभाग का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव।

(सत्ताईस) प्रबंध निदेशक, यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन।

(अट्ठाईस) नगर निगम लखनऊ के दो अधिकारी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए।

(उनतीस) ऐसी संख्या में अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, जो दस से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

गैर सरकारी सदस्य:-

(एक) विधान परिषद के तीन सदस्य और विधान सभा के पाँच सदस्य, अध्यक्ष और सभापति के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(दो) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के चार सदस्य प्रतिनिधि।

(तीन) कृषक/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों यथा-अवध चेंबर ऑफ कामर्स, उद्योग व्यापार मण्डल आदि के चार सदस्य प्रतिनिधि।

(चार) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य।

(2) गैर सरकारी सदस्य, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों, कृषकों/सेवा उपक्रमों/फुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। उक्त नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) उपयुक्तता के आधार पर, उक्त गणमान्य व्यक्तियों का एक पैनल राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पैनल में विहित संख्या से डेढ़ गुना संख्या होगी ताकि रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से आवश्यकतानुसार भरा जा सके।

(4) परिषद में उतनी संख्या में सरकारी या गैर सरकारी सदस्य होंगे जो दस से अधिक न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

4—कोई सदस्य, राज्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित करके स्वयं द्वारा लिखित रूप में नोटिस देकर राज्य परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

राज्य परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र

5—(1) नियम-4 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा उसी श्रेणी के सदस्यों में से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।

त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति

(2) किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, केवल उसी अवधि तक के लिये पद धारण करेगा जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति न हुई होती तो मूल सदस्य उक्त पद पर धारित रहता।

6—राज्य परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी:-

राज्य परिषद की प्रक्रिया धारा 6(3) एवं 6(4)

(क) राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, राज्य परिषद, परिषद की उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अपने किसी सदस्य का चयन करेगी।

(ख) राज्य परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, राज्य आयोग द्वारा किया जायेगा। राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 10 दिनों की अवधि की लिखित नोटिस जारी कर बुलायी जाएगी।

(ग) राज्य परिषद की प्रत्येक नोटिस में, बैठक का स्थान, बैठक का दिनांक और समय विनिर्दिष्ट किया जायेगा और वहां पर किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण भी दिया जाएगा।

(घ) राज्य परिषद की कोई कार्यवाही केवल मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद के गठन में कोई त्रुटि थी।

(ङ) अधिनियम के अधीन संपादित किए जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद, जैसा आवश्यक समझे, स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कृत्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(च) गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु और वापसी के लिये प्रथम श्रेणी का रेल किराया या वायुयान किराया, जो भी कम हो, प्रचलित दर पर प्राप्त करने के हकदार होंगे। विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते उन्हीं दरों पर संदेय होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हों। इसका भुगतान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा किया जायेगा।

(छ) राज्य परिषद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।

(ज) राज्य परिषद द्वारा पारित संकल्प सिफारिशी प्रकृति के होंगे।

जिला उपभोक्ता  
संरक्षण परिषद का  
गठन धारा 8(2)

7—(1) प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी जो कि एक सलाहकार परिषद होगी जिसमें तेरह सरकारी सदस्य तथा बारह गैर सरकारी सदस्य निम्नवत् होंगे:-

#### सरकारी सदस्य-

(एक) जिले का कलेक्टर, जो उसका अध्यक्ष होगा।

(दो) जिला पूर्ति अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट(नागरिक आपूर्ति)।

(तीन) मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

(चार) जिला औद्योगिक केन्द्र का प्रभारी अधिकारी।

(पाँच) जिला कृषि अधिकारी।

(छः) जिला सूचना अधिकारी।

(सात) उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।

(आठ) विकास प्राधिकरण/आवास विभाग का जिला स्तर का अधिकारी।

(नौ) दूरसंचार विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी।

(दस) नगर निगम का नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद का अधिशासी अधिकारी।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का जिला स्तरीय अधिकारी।

(बारह) पेट्रोलियम कम्पनियों का जिला स्तरीय अधिकारी/समन्वयक।

(तेरह) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।

#### गैर सरकारी सदस्य-

(एक) उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(दो) कृषकों/सेवा उपक्रमों/विनिर्माताओं/फुटकर विक्रेताओं/ प्रमुख कारबार सम्बंधी संगठनों के प्रतिनिधियों में से चार सदस्य।

(तीन) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से चार सदस्य।

(2) बारह गैर सरकारी सदस्यों का नाम निर्देशन जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8—कोई सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्वयं द्वारा लिखित नोटिस देकर जिला परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।

जिला परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र

9—(1) नियम 8 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रक्ति को जिला कलेक्टर द्वारा सदस्यों की उसी श्रेणी में से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जायेगा।

त्यागपत्र के कारण हुई रक्ति

(2) नियम 8 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण हुई रक्ति को भरने के लिए नियुक्त व्यक्ति केवल उसी अवधि तक के लिये पद धारण करेगा जिस अवधि के लिए, यदि रक्ति न हुई होती तो मूल सदस्य उक्त पद पर धारित रहता।

10. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद अपने कारबार के संव्यवहार के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी अर्थात्:-

जिला परिषद की प्रक्रिया धारा 8 (3) एवं (4)

(क) जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी और जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में जिला परिषद अपनी बैठक की अध्यक्षता करने के लिये किसी सदस्य का चयन करेगी।

(ख) जिला परिषद की बैठक का संचालन अध्यक्ष, जिला आयोग द्वारा किया जायेगा। जिला परिषद की प्रत्येक बैठक, प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से प्रत्येक सदस्य को अन्यून दस दिन की लिखित नोटिस देकर आहूत की जायेगी।

(ग) जिला परिषद की बैठक में प्रतिभाग करने हेतु सदस्यों को कोई मानदेय संदेय नहीं होगा।

(घ) जिला परिषद के बैठक की प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान, दिनांक और समय विनिर्दिष्ट होगा और बैठक में किए जाने वाले कारबार सम्बंधी संव्यवहार का विवरण अन्तर्विष्ट होगा।

(ङ) जिला परिषद की कोई कार्यवाही, परिषद के गठन में कोई रक्ति या कोई त्रुटि विद्यमान होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(च) जिला परिषद, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से ऐसा कार्य दल गठित कर सकती है, जैसा कि वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक कार्य दल ऐसे कृत्यों को करेगा जो उसे जिला परिषद द्वारा समनुदेशित किए जायें। ऐसे कार्यदलों के निष्कर्ष जिला परिषद के विचारार्थ उसके समक्ष रखे जायेंगे।

(छ) जिला परिषद द्वारा पारित संकल्प, सिफारिश की प्रकृति का होगा।

11—राज्य परिषद एवं जिला परिषद के गैर सरकारी सदस्य, अपने नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

राज्य परिषद एवं जिला परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

12—राज्य परिषद की बैठक साधारणतया राजधानी क्षेत्र लखनऊ एवं जिला परिषद की बैठक सम्बन्धित जिले में आयोजित की जायेगी।

राज्य परिषद एवं जिला परिषद की बैठक

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/C.P. 449/LXXXIV-2-2021-C.N. 1317087, dated January 5, 2022:

No. 2/C.P. 449/LXXXIV-2-2021-C.N. 1317087

*Dated Lucknow, January 5, 2022*

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 102 and clauses (c), (d), (e) and (f) of sub-section (2) of section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

**THE UTTAR PRADESH STATE CONSUMER PROTECTION COUNCIL AND  
DISTRICT CONSUMER PROTECTION COUNCIL RULES, 2021**

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Consumer Protection Council and District Consumer Protection Council Rules, 2021. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
Definitions	2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires- a. "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (Act no. 35 of 2019); b. "State Council" means the State Consumer Protection Council; c. "District Council" means the District Consumer Protection Council; d. "Chairperson" means the Chairperson of the State Consumer Protection Council and the District Consumer Protection Council. (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
Constitution of State Council Section 6 (2)	3. (1) The State Council shall be an Advisory Council consisting of twenty-nine official members and twenty non-official members, as given below:- <b><u>Official Members:-</u></b> i. The Minister in charge of Consumer Protection and Weight and Measurement Department in the State Government will be the Chairperson. ii. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Food and Civil Supplies Department. iii. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Industries Department. iv. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Medical and Health Department. v. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Agriculture Department. vi. Commissioner, Food and Civil Supplies Department. vii. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Transport Department. viii. Principal Secretary, Judicial and Legal Remembrancer to the State Government. ix. General Manager, Telecommunication. x. Chairman, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttar Pradesh. xi. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Avs Vibhag. xii. Director of Information, Uttar Pradesh. xiii. Drug Controller, Uttar Pradesh. xiv. Managing Director, Uttar Pradesh Food and Essential Commodities Corporation, Uttar Pradesh.

- xv. Managing Director, Provincial Cooperative Federation, Uttar Pradesh.
- xvi. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Institutional Finance Department.
- xvii. Managing Director, Rajya Mandi Parishad, Uttar Pradesh.
- xviii. Executive Director, Uttar Pradesh Employees Welfare Corporation.
- xix. Regional Officer, Indian Standard Organisation, Uttar Pradesh.
- xx. State Co-Ordinator, Indian Oil Corporation Uttar Pradesh.
- xxi. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Nagar Vikas Vibhag, Uttar Pradesh.
- xxii. Secretary, Uttar Pradesh State Electricity Board, Lucknow.
- xxiii. Divisional Manager, Northern Railway, Lucknow.
- xxiv. Anchalik Prabandhak Life Insurance Corporation.
- xxv. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Cooperative Department Uttar Pradesh Shasan.
- xxvi. Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the Government in the Information Department.
- xxvii. Managing Director, Uttar Pradesh Development System Corporation.
- xxviii. Two officers from Nagar Nigam, Lucknow to be nominated by the Chairperson.
- xxix. Such number of other official or non official Members, not exceeding ten as may be nominated by the Central Government.

#### **Non-Official Members:-**

- i. Three members of the Legislative Council and five members of the the Legislative Assembly will be nominated by the State Government with the approval of the Speaker/Chairman.
- ii. Four member representatives of voluntary organizations/agencies representing consumer interests.
- iii. Four member representatives of farmers/service undertakings/retailers and major business organizations like Avadh Chamber of Commerce, Udyog Vyapar Mandal, etc.
- iv. Four members from amongst eminent persons working in the field of consumer protection or in an important area of the society.

(2) Non-Official Members shall be nominated from the representatives of voluntary organizations/ agencies representing the interests of consumers, farmers/ service undertakings/ retailers and representatives of major business organizations and eminent members working in the field of consumer protection or in important areas of the society. The said nomination will be done by the State Government.

(3) On the basis of suitability, a panel of the said dignitaries will be prepared by the State Consumer Disputes Redressal Commission and be made available to the State Government. It will be ensured by the State Consumer Disputes Redressal Commission that there will be one and a half times the prescribed number in the said panel so that the vacancies can be filled from the waiting list as per need.

(4) The Council may consist of such number of official or non-official members, not exceeding ten, as may be nominated by the Central Government.

4. Any member may, by giving notice in writing by himself addressed to the Chairperson of the State Council, resign from the State Council.

Resignation  
of members  
of State Council

5. (1) The vacancy caused by the resignation of a member under rule 4 shall be filled by the State Government through fresh appointment from the same category of members.

Vacancy caused  
by resignation

(2) A person appointed to fill a vacancy caused by the resignation of a member shall hold office only for the period for which, if the vacancy had not arisen, the original member would hold office had the vacancy not occurred.

Procedure of State Council <i>Section 6(3) and 6(4)</i>	<p>6. The State Council shall observe the following procedure in relation to the transaction of its business:-</p> <p>a. The meeting of the State Council shall be presided over by the Chairperson . In the absence of the Chairperson , the State Council shall choose one of its members to preside over that meeting of the Council.</p> <p>b. The meeting of the State Council will be conducted by the Chairman, State Commission. Every meeting of the State Council shall be convened by issuing a written notice to each member for a period of not less than ten days from the date of issue of the notice.</p> <p>c. Every notice of the State Council shall specify the place of meeting, the day and time of the meeting and shall also give a description of the business transacted therein.</p> <p>d. No proceeding of the State Council shall be invalid merely by reason of existence of any vacancy therein or any defect in the constitution of the Council.</p> <p>e. For the purposes of performing the functions under the Act, the State Council may constitute a working group from amongst its members as it deems necessary and the working group so constituted shall perform such functions as may be placed before it for the consideration of the State Council.</p> <p>f. The non-official members shall be entitled to receive first class rail fare or air fare, whichever is less, at the prevailing rate in connection with journeys undertaken to and from for the purpose of attending the meetings of the State Council. Traveling and daily allowances will be payable to the members of the Legislative Assembly/Legislative Council at such rates as are admissible to such members. It will be paid by the State Consumer Disputes Redressal Commission.</p> <p>g. No honorarium shall be payable to the members for attending the meetings of the State Council.</p> <p>h. The resolutions passed by the State Council shall be of a recommendatory nature.</p>
Constitution of District Consumer Protection Council <i>Section 8(2)</i>	<p>7. (1) There shall be a District Consumer Protection Council in each district which will be an advisory council consisting of thirteen official and twelve non-official members, namely:-</p> <p><b><u>Official Members :-</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Collector of the district who shall be its Chairperson.</li> <li>District Supply Officer/Additional District Magistrate (Civil Supply).</li> <li>Chief Medical Officer.</li> <li>Officer in charge of District Industrial Centre.</li> <li>District Agriculture Officer.</li> <li>District Information Officer.</li> <li>Assistant Regional Transport Officer of Transport Department of Uttar Pradesh.</li> <li>District Level Officer of Development Authority/Housing Department.</li> <li>District Officer of Telecom Department.</li> <li>Nagar Ayukt of Nagar Nigam/Executive Officer of Nagar Palika Parishad.</li> <li>District Level Officer of Uttar Pradesh Power Corporation.</li> <li>District Level Officer/ Co-ordinator of Petroleum Companies.</li> <li>Chairman, District Consumer Disputes Redressal Commission.</li> </ol> <p><b><u>Non-Official Members:-</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Four members from representatives of voluntary organizations/ agencies representing consumer interests.</li> <li>Four members from representatives of farmers/service undertakings/ manufacturers/retailers/major business organizations.</li> <li>Four members from eminent persons working in the field of consumer protection or in important areas of the society.</li> </ol>



(2) Nomination of twelve non-official members will be done by the District Collector.

8. Any member may resign from the District Council by giving notice in writing by him addressed to the Chairperson of the District Council.

Resignation of  
members of  
District Council

9 (1) The vacancy caused by the resignation of a member under rule 8 shall be filled by the District Collector through fresh appointment from the same category of members.

Vacancy caused  
by resignation

(2) A person appointed to fill a vacancy created by the resignation of a member under rule 8 shall hold office only for the period for which, if the vacancy had not arisen, the original member would have remained in office.

10. The District Consumer Protection Council shall follow the following procedure in relation to the transaction of its business, namely:-

Procedure of  
District Council  
Section 8(3) and  
8(4)

a. The meeting of the District Council shall be presided over by the District Collector and in the absence of the District Collector, the District Council shall choose a member to preside over its meeting.

b. The meeting of the District Council will be conducted by the Chairperson, District Commission. Every meeting of the District Council shall be called by giving a written notice of not less than ten days to every member from the date of its issue.

c. No honorarium will be payable to the members for attending the meeting of the District Council.

d. Every notice of a meeting of the District Council shall specify the place, day and time of the meeting and shall contain a description of the business transacted at the meeting.

e. No proceeding of the District Council shall be invalid by reason of the existence of any vacancy or any defect in the constitution of the Council.

f. The District Council may, for the purpose of performing its functions under the Act, constitute such working group from amongst its members as it may consider necessary and every working group so constituted shall perform such functions as may be assigned to it by the District Council. The findings of such working groups shall be placed before the District Council for its consideration.

g. The resolution passed by the District Council shall be in the nature of recommendation.

11. The non-official members of the State Council and District Council shall hold office for a period of three years from the date of their nomination.

Term of non-  
official  
members of  
State Council  
and District  
Council

12. The meeting of the State Council will generally be held in the capital region Lucknow and the meeting of the District Council will be held in the respective district.

Meeting of State  
Council and  
District Council

By order,  
VEENA KUMARI,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 547 राजपत्र-2022-(1210)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप-2022-(1211)-900 प्रतियां (कम्प्यू०/टी०/आ०)।